- 20th Year
- Issue: 159
- 15.10.2026 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

लद्दाख में रणनीतिक कनेक्टिविटी होगी मजबूत, पीएम मोदी करेंगे ३३५० करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन

१४/१० (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वे 15 अज़्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। एज़्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में लेह के कुशोक बकुला रिज़्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और निज़्मू-पदुम-दारचा रोड शामिल हैं, जो कनेज़्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को मज़बूत करेंगे। मोदी ने एज़्स पर लिखा कि कल, 15 अज़्टूबर को, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेज़्ट्स का उद्घाटन और उन्हें देश को समर्पित करूंगा। इनमें शामिल हैं- लेह में कुशोक बकुला रिज़्पोचे एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग; निज़्मू-पदुम-दारचा रोड, जो कनेज़्टिविटी और रणनीतिक आवाजाही को बेहतर बनाएगा। इन प्रोजेज़्ट्स में 9 MW का हनु हाइड्रोइलेज़्ट्रिक प्रोजेज़्ट और पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेह में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, और प्रोजेज़्ट अमृत हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 जल निकाय भी शामिल हैं।

उन्होंने आगे लिखा 9 MW का हनु हाइड्रोइलेज़्ट्रिक प्रोजेज़्ट और पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर; लेह में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क; प्रोजेज़्ट अमृत हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 जल निकाय। मोदी ने कहा कि ये प्रोजेज़्ट्स कनेज़्टिविटी को मजबूत करेंगे, डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, लद्दाख की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेंगे और वहां के लोगों के जीवन की गुणवज़्ा में सुधार करेंगे।

उन्होंने कहा, ये प्रोजेज़्ट्स कनेज़्टिविटी को मजबूत करेंगे, डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, समृद्ध विरासत को संरक्षित करेंगे और लोगों के जीवन की गुणवज़्ा में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दोपहर करीब 12-30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ के पांच बड़े डेवलपमेंट प्रोजेज़्ट्स का उद्घाटन करेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये पांच प्रोजेज़्ट्स कनेज़्टिविटी को मजबूत करेंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेंगे और क्षेत्र में जल सुरक्षा को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री लेह के कुशोक बकुला रिज़्पोचे एयरपोर्ट पर ?640 करोड़ की लागत से बनी नई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 23,800 वर्ग मीटर में फैले इस आधुनिक टर्मिनल को हर साल 35 लाख यात्रियों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, यह सुविधा लद्दाख के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को दिखाती है। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के मेल से बना यह टर्मिनल यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाएगा और देश के बाकी हिस्सों के साथ हवाई कनेज़्टिविटी को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा बनाई गई 298 किलोमीटर लंबी निज़्मू-पदुम-दारचा सड़क को देश को समर्पित करेंगे। दूर-दराज़ ज़ंस्कार घाटी से होते हुए लेह में निज़्मू को हिमाचल प्रदेश में दारचा से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक कनेज़्टिविटी कॉरिडोर देती है, जो श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह हाईवे के साथ-साथ काम करेगी। ऊँचाई पर स्थित शिंकुन ला पास समेत हिमालय के मुश्किल रास्तों से गुज़रने वाली यह सड़क इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलज़्धि है। इसकी रणनीतिक अहमियत सेना के लिए ऑपरेशनल मोबिलिटी बढ़ाने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को मजबूत करने में है। इससे ज़ंस्कार के लोगों को भी हेल्थकेयर, शिक्षा, बाज़ार और ज़रूरी सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिलेगी।

आप देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब एयरपोर्ट पर सीजेपी के अभिजीत दिपके को लोगों ने घेरा

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): दिल्ली पहुँचने पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के एक वीडियो में दिख रहा है कि जब दिपके बाहर निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति उन पर चिल्ला रहा था। वीडियो में एक व्यक्ति दिपके पर चिल्लाते हुए पूछता है, आप देश को ज़्यों बर्बाद कर रहे हैं? CJP नेता मुस्कुराते हुए और विरोध करने वाले व्यक्ति को थंज़्स-अप का इशारा करते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं।दिपके बुधवार दोपहर महाराष्ट्र में अपने गृहनगर से राजधानी लौटे, जहाँ वे 10 अज़्टूबर को अपनी दादी के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। 10 अज़्टूबर को मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली पहुँचने पर, दिल्ली पुलिस ने उन्हें ज़्लाइट से ही हिरासत में ले लिया था। राजधानी लौटने पर, डिपके ने अपने साथियों आशुतोष रांका और सौरव दास को पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

दिपके ने गिरज़्तारी और पांच दिन की हिरासत की आलोचना करते हुए पूछा कि ज़्या देश में तिरंगा फहराना कोई अपराध है। दिपके ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि ज़्या तिरंगा फहराना कोई अपराध है? आशुतोष और सौरव को पांच दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ज़्यों? ज़्योंकि वे जंतर-मंतर गए और तिरंगा फहराया। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश शासन के दौरान, जो स्वतंत्रता सेनानी सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराते थे, उन्हें गिरज़्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। सामाजिककार्य से जुड़ें

मंगलवार सुबह ष्टछ्वक्क सदस्यों को जंतर-मंतर पर अचानक विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरज़्तार कर लिया गया; वे वहाँ पहुँचने के लिए एक गेट पर चढ़े थे। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के एक दिन बाद हुआ, जबकि वहाँ पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दीपके द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में ष्टछ्वक्क स्वयंसेवकों (जिनमें रंका और दास भी शामिल थे) को जंतर-मंतर पहुँचने के लिए गेट पर चढ़ते हुए दिखाया गया।

मतगणना का वीडियो की गायब हो गया... सुको ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा-बेतुके बहाने नहीं सुनेंगे

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग के इस दावे पर कड़ी आपज़ि जताई कि वह कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 में हुई वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं ढूंढ पाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आयोग उपलज़्ध रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने श्वष्टद्ध से कहा कि भारत का चुनाव आयोग (श्वष्टद्ध) यह कैसे कह सकता है कि उसने अपना रिकॉर्ड खो दिया है? आपका मुज़्य काम चुनाव कराना है और आपके पास डॉज़्यूमेंट होने ही चाहिए। यह कहने का ज़्या मतलब है कि %हां, हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं%? आपने उसे चुने हुए उज़्मीदवार को दे दिया था। रिकॉर्ड की कोई कस्टडी ही नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे अगली तारीख पर पेश करें। वरना, हमें आपके खिलाफ़ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। हम इस तरह के कमजोर बहाने स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उज़्मीदवार डीएन जीवराज को 201 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, लेकिन बाद में उस निर्वाचन क्षेत्र में पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। स्जब राजेगौड़ा ने चुनाव ऑज़्ज़र्वर की रिपोर्ट और 2023 में हुई ओरिजिनल गिनती और इस साल मई में हुई दोबारा गिनती के वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की मांग की, तो श्वष्टद्ध ओरिजिनल गिनती की फुटेज का पता लगाने में नाकाम रही, जिस पर बेंच ने उसे फटकार लगाई। जब कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखा, तो श्वष्टद्ध की ओर से पेश सीनियर वकील शेषद्रि नायडू ने कहा कि ओरिजिनल गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकी। इस दलील से बेंच संतुष्ट नहीं हुई और उसने आयोग से कहा कि अगली सुनवाई तक जो भी रिकॉर्ड उपलज़्ध हों, उन्हें पेश किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2027 तय की। गायब फुटेज इसलिए अहम है ज़्योंकि विवाद पोस्टल बैलेट के साथ किए गए व्यवहार और उस प्रक्रिया की वैधता पर केंद्रित है, जिसके कारण राजेगौड़ा की चुनावी जीत पलट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई में श्वष्टद्ध को निर्देश दिया था कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर हुई दोबारा गिनती से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड पेश करे और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उठाए गए सभी संबंधित कदमों को आगे की जांच तक रोक दे। यह विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट में जीवराज द्वारा दायर एक चुनावी याचिका से शुरू हुआ.

जो अमेठी में अपने दम पर चुनाव तक नहीं लड़ सकता, वह शहंशाह बनाने के लिए..., स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज

अमेठी १४/१० (संवाददाता): समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमेठी में हुए एक सदस्यता समारोह में, तीनों ने पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने के लिए बीजेपी के टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया। इसके बाद, राज्य अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायकों को पार्टी का स्कार्फ पहनाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आप चाहें जितनी भी पार्टियों को एक साथ ले आएं और अपने राजकुमार को सम्राट बनाने की कोशिश करें, लेकिन उज़्र प्रदेश की सच्चाई यह है कि कांग्रेस लगातार नौ विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अमेठी इस बात का गवाह है कि अगर कांग्रेस का वह परिवार इस इलाके में अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वह अकेले देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूँगी- जो व्यक्ति (राहुल गांधी) अमेठी से अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता, वह आज दिल्ली में 14 राजनीतिक दलों को बुलाकर उन्हें देश का शहंशाह बनाने के लिए कह रहा है। यह लोकतंत्र सिस्टम, संविधान और चुनाव आयोग के खिलाफ़ ऐसी गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बागी स्क्र विधायकों के BJP में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि आज उज़्र प्रदेश में तीन बड़े नेताओं ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है। ब्द्ब्क्ककार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं... समाजवादी पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गई थी। उन्हें सपने देखने का पूरा अधिकार है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि BJP की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ BJP कार्यकर्ता इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि उज़्र प्रदेश की जनता भी कभी नहीं भूलेगी कि स्क्र के शासन का मतलब देश के विकास को रोकना था। आज उज़्र प्रदेश में 5.94 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है। ये तीनों विधायक 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। हालाँकि, फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने अपनी पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर बीजेपी उज़्मीदवार के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की।

पति को मार कर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान को फांसी

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): मेरठ के चर्चित %ज़्लू ड्रम मर्डर केस% में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुज़्ला को मौत की सज़ा सुनाई गई। 30 सितंबर को अदालत ने दोनों ही आरोपियों को दोषी ठहराया था। सजा के ऐलान के वक्त मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो वहीं कोर्ट रूम में मृतक सौरभ की मां रेणु और भाई बबलू भी मौजूद रहे। इसी बीच, कोर्ट में मुस्कान के माता-पिता के एक बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अदालत को लिखित में दिया कि सौरभ एक बेहद सीधा और अच्छा लड़का था, जिसकी बेरहमी से जान ली गई। परिवार ने साफ कह दिया कि अगर अदालत मुस्कान को फांसी के फंदे पर भी लटका देती है, तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा; वो उससे सारे रिश्ते खत्म कर चुके हैं। बता दें कि जेल में बंद रहने के दौरान भी परिवार ने कभी मुस्कान से मुलाकात नहीं की थी। वेडिंगप्लानर चुनें

मेरठ के ज़्लू ड्रम मर्डर केस में मर्चेंट नेवी के 29 साल के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या का मामला शामिल है। आरोप है कि उनकी हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के साथी रहे प्रेमी साहिल शुज़्ला ने की थी। बताया जाता है कि दोनों 2019 में एक ङ्खद्धड्डह्लह्यश्वश्च ग्रुप के ज़रिए दोबारा संपर्क में आए और बाद में उनके बीच रिश्ता बन गया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने सौरभ की हत्या की योजना बनाने में कई महीने बिताए, ज़्योंकि वे उन्हें अपने रिश्ते में रुकावट मानते थे। यह अपराध कथित तौर पर मार्च 2025 में किया गया था, जब सौरभ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से भारत लौटे थे।

जेएनयू की ११ छात्राओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची भाजपा

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया के. रहाटकर ने भरोसा दिलाया है कि वह कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 11 छात्राओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेंगी। चौधरी ने यह बात तब कही जब एक प्रतिनिधिमंडल ने रहाटकर से मुलाकात की और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

यहां NCW चेयरपर्सन से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पांच सांसदों और बीजेपी महिला विंग के पदाधिकारियों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में कार्रवाई और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग से संपर्क किया। बैठक के नतीजे के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा हमें भरोसा दिलाया गया है कि हालात को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगी। चौधरी ने कहा कि छात्राओं ने मई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और अपने आरोप सामने लाने के लिए उनकी तारीफ़ की। हमें हाल ही में छ्वहृ में हुई घटना पर ध्यान देना चाहिए, ज़्योंकि छ्वहृ के एक प्रोफ़ेसर और मणिपुर के कांग्रेस सांसद ने 11 युवतियों और छात्राओं के साथ बुरा बर्ताव किया था, और उन लड़कियों ने बहादुरी से मई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उस सांसद को बचा रही है। उन्होंने कहा, जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण के कारण, कांग्रेस नेताओं ने अभी तक उनके बारे में एक शज़्द भी नहीं कहा है। ऐसा इसलिए है ज़्योंकि वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है और उसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल है। शिकायत करने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लड़कियाँ सुरक्षित रहें और उन्हें भविष्य में किसी तरह का नुकसान न हो। उन्होंने आगे कहा चूंकि वह लोकसभा में सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस को नियमों के अनुसार हमारी युवतियों की सुरक्षा और सज़्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें पार्टी से नहीं निकाला है।

उन्होंने कहा हमारा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को इतने पवित्र स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम आज अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला आयोग से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह करने के लिए यहां आए हैं। JNU ने POSH नियमों के तहत जांच के बाद अपनी आंतरिक समिति की बड़ी सज़ा की सिफारिश पर 9 अज़्टूबर को अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सांसद ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जांच रिपोर्ट की प्रति न देने का आरोप लगाया है, जो उनके अनुसार अपील करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने POSH अधिनियम की धारा 16 के तहत गोपनीयता के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनकी पहचान समय से पहले उजागर कर दी गई थी।

विविध समाचार

भारतीय जहाजों पर लगातार हमलों से भड़का भारत ! अजीत डोवाल ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी घुमाया फोन

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): पश्चिम एशिया में युद्ध की आग अब भारत के समुद्री हितों और नागरिकों की सुरक्षा तक पहुंच गई है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में भारतीय नाविकों को लेकर जा रहे दो व्यापारिक जहाजों पर हमलों के अगले ही दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रज़ाई से फोन पर बातचीत की। 12 अज़्टूबर 2026 को हुई इस उच्चस्तरीय वार्ता का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जिस समय यह संपर्क हुआ, उसने भारत-ईरान सुरक्षा संवाद के सामरिक महत्व को फिर केंद्र में ला दिया है। भारतीय जहाजों पर लगातार बढ़ते हमलों और भारतीय नाविकों की जान पर मंडराते खतरे ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में दो व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अब भारत की सुरक्षा कूटनीति सीधे सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 12 अज़्टूबर को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रज़ाई से फोन पर बातचीत की। ईरान के सज़्ा और सुरक्षा तंत्र में अहम भूमिका रखने वाले रज़ाई तक डोभाल का सीधा पहुंचना ऐसे समय में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जब समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ रहा है और दो भारतीय नाविक अब भी लापता हैं। इस उच्चस्तरीय संपर्क ने साफ कर दिया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार के हितों को लेकर नई दिल्ली कूटनीतिक स्तर पर पूरी सक्रियता से जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि 11 अज़्टूबर को दो वाणिज्यिक जहाज हमलों की चपेट में आए। निकारागुआ के ध्वज वाले टैंकर रूञ्ज क्व्हल्ह्थ ष्ठश्द्यश्चद्धद्वठ्ठ पर ड्रोन से हमला हुआ। जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से नौ को बचा लिया गया, जबकि दो लापता बताए गए। दूसरी ओर, मार्शल द्वीप के ध्वज वाले MT Valthera पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई। उस पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तत्काल तनाव कम करने और बातचीत के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने की मांग की। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले बंद होने चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान के अधिकारियों और संबंधित जहाज प्रबंधन कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है। देखा जाये तो यह केवल दो जहाजों की सुरक्षा का मामला नहीं है। समुद्र में फंसे भारतीय नागरिकों की जान, भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था और पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति, तीनों दांव पर हैं। ईरानी दूतावास के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। देखा जाये तो संकट के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर सीधा संपर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ईरान के सर्वोच्च नेता के बेहद करीबी भी बताये जाते हैं। इसलिए इस स्तर के संवाद के जरिए भारत अपने सुरक्षा सरोकारों को संबंधित पक्ष के सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र तक पहुंचा सकता है, घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांग सकता है और भारतीय नागरिकों तथा व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश सकता है।

यहीं डोभाल की भूमिका का वास्तविक रणनीतिक महत्व सामने आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संकटों में केवल सार्वजनिक बयान देना पर्याप्त नहीं होता; संवेदनशील संपर्क चैनलों को सक्रिय रखना भी जरूरी होता है। ईरान के साथ संवाद बनाए रखना भारत को अपनी चिंताओं को सीधे रखने और संभावित जोखिमों पर बातचीत करने का अवसर देता है। इस पहल की सफलता का वास्तविक पैमाना हालांकि लापता नाविकों की सुरक्षित वापसी, जहाजों की सुरक्षा और समुद्री आवाजाही में सुधार होगा।

हम आपको बता दें कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। युद्ध से पहले वैश्विक तेल और गैस व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इस संकरे समुद्री गलियारे से गुजरता था।

यहां नाकेबंदी, बारूदी सुरंगों या जहाजों पर हमलों का असर क्षेत्रीय सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच सकता है। ईरान ने मार्च 2026 से जारी संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर नाकेबंदी लागू की है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने चेतावनी दी है कि नेविगेशन और पहचान प्रणाली बंद करके गुजरने वाले जहाजों को शत्रुतापूर्ण माना जा सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक अन्य तेल टैंकर के समुद्री बारूदी सुरंग से टकराने की भी खबर दी है। ये घटनाएं समुद्री जोखिमों की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। साथ ही इस स्थिति का भारत के लिए सीधा अर्थ है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का खतरा, माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि तथा ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंका। समुद्री संकट जितना लंबा खिंचेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका दबाव उतना बढ़ सकता है।

देखा जाये तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की सितंबर में भारत यात्रा और ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन के संदर्भ में हुए संपर्कों के बाद डोभाल-रज़ाई वार्ता भारत-ईरान संवाद की निरंतरता को दर्शाती है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी पहले ईरानी विदेश मंत्री अज़्बास अराघची से बातचीत में नागरिकों की मौजूदगी वाले जहाजों पर हमले रोकने की जरूरत उठा चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए चुनौती स्पष्ट है। ईरान के साथ संवाद बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है वह भी बिना किसी सैन्य टकराव में अनावश्यक रूप से उलझे हुए। वैसे यह संतुलन आसान नहीं है, ज़्योंकि क्षेत्र में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के साथ अन्य क्षेत्रीय तनाव भी जुड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत वैश्विक नाविक कार्यबल में लगभग 12.16 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। उपलज़्ध रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 139 भारतीय होर्मुज़ क्षेत्र में फंसे हुए बताए गए हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में कम से कम 11 भारतीय नाविकों की मौत की भी सूचना दी गई है। ये आंकड़े समुद्री सुरक्षा को भारत की विदेश नीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत दिखाते हैं। बहरहाल, होर्मुज़ में संकट भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों की जान, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार से जुड़ी वास्तविक चुनौती है। डोभाल की ईरानी समकक्ष से बातचीत इस चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण संवाद-चैनल है। लेकिन अब असली कसौटी परिणाम होंगे। लापता नाविकों का पता लगाना, भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि पश्चिम एशिया का युद्ध भारत के समुद्री हितों को और नुकसान न पहुंचाए, बहुत जरूरी है।

सपा पर बरसे सीएम योगी, माफिया के खात्मे पर विपक्ष को होती है तकलीफ

बरेली १४/१० (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और आत्म-सज़्मान राज्य सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि डबल-इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रही है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना करने के बाद, आदित्यनाथ ने %ङ्ग% पर लिखा कि डबल-इंजन% सरकार की हर पहल महिलाओं को सज़्मानजनक जीवन दिलाने के लिए समर्पित है। बरेली में एक कार्यक्रम में योगी ने कहा कि यूपी बदल चुका है। लोग बेझिझक, निडर होकर घर के बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षा का एक माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के प्रति लोगों की धारणा बदलने में सफलता प्राप्त की है। विपक्ष पर वार करते हुए योगी ने कहा कि जिन लोगों ने बुराई पाली थी, जनता ने उनको जवाब दे दिया और जो अच्छाई लेकर चले थे, वे प्रदेश को भी अच्छा बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के फैसले भी बुलेट इंजन की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, बरेली में दंगा शुरू हो जाता था। अब दंगाई जेल के अंदर उर्स मनाने का काम कर रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा विरोधी थे, वे शिक्षकों के हितैषी कहां से हो सकते हैं। जो शिक्षा का सज़्मान करेगा, वही शिक्षकों का सज़्मान भी करेगा। जब सरकार माफिया मुक्ति का अभियान चलाती है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को होती है। योगी आदित्यनाथ ने बरेली में घोषणा की कि राज्य के 68,000 ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) का मानदेय बढ़ाया जाएगा। ग्राम प्रहरियों को पहले ?2,500 मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर ?3,500 कर दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें और उनके परिवारों को ?5 लाख तक का कैशलेस इलाज भी मिलेगा। योगी ने कहा कि जो लोग पहले सज़ा में थे, वे ही लूट-पाट में शामिल थे। ऐसे में किसे गिरज़्तार किया जा सकता था? जो लोग गाइड थे, वे ही चोर थे। लेकिन अब उज़र प्रदेश बदल गया है, ज़्योंकि अब कोई दंगा या अशांति नहीं होती। माफियाओं का सफाया हो गया है। योगी ने कहा कि यह ज़रूरी है कि अपराधियों में कानून का डर हो। अगर अब कोई किसी बेटी पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो यमराज उसे अगले चौराहे पर यमलोक भेजने की तैयारी कर लेंगे। अगर कोई चेन-स्नैचिंग करेगा, तो अगले चौराहे पर उसका लंगड़ा होना तय है। इससे पहले, मुज़्यमंत्री योगी ने बरेली ज़ोन के 7,000 ग्राम प्रहरियों को सज़्मानित किया और उन्हें इनाम के तौर पर मोबाइल फ़ोन दिए। दोपहर करीब 2 बजे, योगी शिक्षकों के एक सज़्मेलन में शामिल होंगे और नौ ज़िलों के शिक्षकों को संबोधित करेंगे। वह उनसे शिक्षकों के स्नष्ट उज़्मीदवार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।

जेएनयु यौन शोषण के में घिरे कांग्रेसी सांसद, भाजपा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की निलंबन की मांग

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): BJP की महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को लोकसभा से सस्पेंड करने के लिए उनसे दखल देने की मांग की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से छ्वहृ में यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व क्च्छ्वक्क सांसद डी. पुरंदेश्वरी ने किया और इसमें चौधरी, दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और अन्य शामिल थीं। यह मुलाकात क्च्छ्वक्क महिला मोर्चा द्वारा दिल्ली में कांग्रेस मुज़्यालय और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने के एक दिन बाद हुई, जिसमें इनर मणिपुर से सांसद अकोइजम को पार्टी से निकालने की मांग की गई थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई महिला सांसदों और क्च्छ्वक्क कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पार्टी के एक सूत्र ने पहले कहा था कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाएगा और उनसे दखल देने की मांग करेगा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि पितृसज़ा को खत्म करने की बात करने के बावजूद वे इस मामले पर चुप रहे।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ़्ते अकोइजम को नौकरी से निकाल दिया, ज़्योंकि उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था। वे छ्वहृ के स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज के तहत सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ सोशल सिस्टज़्स में प्रोफ़ेसर थे।रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई 2026 में कम से कम 11 छात्राओं ने प्रोफ़ेसर के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि अकोइजम छात्राओं को मीटिंग या इकट्ठा होने के बहाने कैंपस में बने अपने घर बुलाते थे और उनका यौन शोषण करने की कोशिश करते थे। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि वे ज़्लास में अश्लील और अनुचित बातें करते थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि पितृसज़ा को खत्म करने की बात करने के बावजूद वे इस मामले पर चुप रहे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ़्ते अकोइजम को नौकरी से निकाल दिया, ज़्योंकि उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था।

राजग से गठबंधन नहीं हुआ तो अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे-राजभर

पटना १४/१० (संवाददाता):राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उज़र प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में उनका राजग से गठबंधन नहीं होता है तो वह मोर्चा बनाकर अवश्य चुनाव लड़ेंगे, इससे उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री पद का लालच नहीं है। राजभर ने शुक्रवार को जिले के नवानगर में सुभासपा की एक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में राजग से अलग चुनाव लड़ने पर उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम कहां कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी तो पहली कोशिश यही है कि हम लोग राजग गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ें।उन्होंने कहा, 2025 में बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यदि गठबंधन नहीं होता है तो फिर मोर्चा बनाकर अवश्य चुनाव लड़ेंगे।

लोकतंत्र को बचाना एकमात्र लक्ष्य, पूरा विपक्ष एकजुट-राहुल गांधी

नयी दिल्ली १४/१० (संवाददाता): इंडिया गठबंधन की हाई टी बैठक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर हुई। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने पिछले चार दिनों में इंडिया गठबंधन की पहलों की ज़बरदस्त सफलता देखी है; राहुल जी और अन्य नेताओं ने जनता के मुद्दों को बहुत गंभीरता और लगन से उठाया। इतनी बड़ी संज़्या में लोग शायद ही कभी इकट्ठा हुए हों। दिल्ली में यह पहली बार है जब युवा और नागरिक पूरी तरह से अपनी पहल पर एक साथ आए हैं। आपने यह देखा है, इसलिए मैं और विस्तार से नहीं बताना चाहता। अब हर कोई मोदी की वोट चुराने की योजना का पर्दाफ़ाश करने के लिए तैयार है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का एक ज़रिया जंतर-मंतर था और अब सरकार ने तय किया है कि जंतर-मंतर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक भावनाएं ज़ाहिर करने के लिए नहीं किया जा सकता। हम इस सोच को चुनौती देने जा रहे हैं। सरकार के लिए यह तय करना इतना आसान नहीं होगा कि भारत के लोग अपनी आवाज़ के लिए लड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने ऐसा किया है-मिस्टर मोदी, जो इसके मुज़्य सूत्रधार हैं; मिस्टर अमित शाह, जो इसे लागू करने वाले हैं; मिस्टर ज्ञानेश कुमार और अन्य - उन्हें यह समझना होगा कि उन पर शिकंजा कस रहा है। यह इतना आसान नहीं होगा कि आप भारतीय संविधान को नष्ट कर दें और बच निकलें।

उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ एक साथ खड़े हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई समानांतर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ़ एक ही विरोध प्रदर्शन है और इस विरोध का एक ही मकसद है- भारत में लोकतंत्र की बहाली। इस देश में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। चुनाव प्रणाली को बर्बाद कर दिया गया है। संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है। हम इस देश में लोकतांत्रिक शासन, यानी असली लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने किस तरह लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है; यह साफ़ तौर पर अमित शाह और मोदी जी की साज़िश है।

हम लोकतंत्र को बचाने के अपने संकल्प पर एकजुट हैं और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, हम देंगे। यह गांधी जी, लोहिया जी, भगत सिंह और कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। फिर भी, कुछ लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं—चाहे वह श्वष्ठ हो, ष्टक्च्ढ्ढ हो या इनकम टैज़्स डिपार्टमेंट—पर कज़्ज़ा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग—और खासकर ज्ञानेश गुप्ता—तो दस कदम आगे निकल गए हैं।

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश गुप्ता ने जिस तरह एक कठपुतली की तरह काम किया है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बच नहीं पाएंगे; वे डरे हुए हैं, और यह डर इस बात से साफ़ झलकता है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन की जगह बदल दी—जंतर-मंतर (ऐतिहासिक महत्व वाली जगह जहाँ पारंपरिक रूप से विरोध प्रदर्शन होते थे) से हटाकर दिल्ली की सीमाओं पर ले गए। यह कदम उनके डर को ज़ाहिर करता है। हम यह लड़ाई जारी रखेंगे; हम एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जिन लोगों ने यह साज़िश रची—चाहे वह मोदी जी हों, ज्ञानेश गुप्ता हों या अमित शाह—जिन्होंने वोटों की चोरी और चुनावों में धांधली करवाई, वे देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब हर नागरिक उनसे हिसाब मांग रहा है; उन्हें अपने कामों का जवाब देना होगा। उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होगी, और हम निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने में सफल होंगे। हृष्टक्क-स्ष्टक्क की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम ढ्ढहृष्ठढ्ढ गठबंधन के हिस्से के तौर पर पूरी ताकत के साथ एकजुट हैं; हमारा संघर्ष जारी रहेगा ज़्योंकि इस देश में संविधान को कमजोर किया गया है और वह अभी खतरे में है।

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में सभी भारतीयों को जो अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा के लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। एक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति इन अधिकारों को कुचलने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम इस अन्याय और दमन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी ताकत से एकजुट हैं; हमारा आंदोलन दिल्ली से लेकर ज़मीनी स्तर तक जारी रहेगा। ढ्ढ्रष्ट की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने कहा कि ध्यान क्च्छ्वक्क पर ही रहना चाहिए और लड़ाई सज़ाधारी पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने ढ्ढहृष्ठढ्ढ गठबंधन के सांसदों के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। ष्टक्क्ढ्ढ के महासचिव डी. राजा ने कहा कि हमने देश के मौजूदा हालात और ष्टश्वष्ट ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग वाले अभियान को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान पूरा देश आंदोलन कर रहा है, देश भर में लोग नाराज़ हैं और विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यह हमारा शहर है, लेकिन हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए। विरोध-प्रदर्शन तो होंगे ही, आप उन्हें दबा नहीं सकते। जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर हटा दिया गया है, हम इसकी निंदा करते हैं; इसे विरोध-प्रदर्शन की जगह बने रहना चाहिए... वे चाहते हैं कि लोग कहाँ जाएँ? हम जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर वापस पाने के लिए लड़ेंगे... लोगों को असहमति जताने का अधिकार है।

विविध समाचार

चने में हेलिकोवर्पा की करें रोकथाम

चने की इल्ली जिसे स्थानीय कृषक पहचानते हैं, विश्व में वैज्ञानिक भाषा में इसे हेलिकोवर्पा के नाम से जाना जाता है। हेलिकोवर्पा जो कि पूर्व में हेलियोथिस के नाम से पुकारा जाता था, इसकी अनेक प्रजातियां सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान हैं (कृषकगण इन प्रजातियों को चने की इल्ली की बहनों के रूप में समझ सकते हैं।

चने की इल्ली के नियंत्रण

प्रबंधन उपाय

कीट के सफल प्रबंधन के लिये नियंत्रण की कोई एक ही विधि अपनाना असफल सिद्ध हुआ है। जैसे केवल रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग से इसका प्रभावी नियंत्रण नहीं होता, इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। अत: वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित समन्वित कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाकर इस कीट के प्रकोप और इससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

❖ ग्रीष्मकालीन जुताई करें ताकि सुप्त अवस्था में भूमि के अंदर पड़ी शंखियाँ, तेज धूप तथा परभक्षी पक्षियों द्वारा नष्ट की जा सकें।

❖ असिंचित चने में बोनी मध्य अक्टूबर तक तथा सिंचित क्षेत्रों में नवम्बर प्रथम सप्ताह तक बोनी करने से कीट प्रकोप कम होता है। समय पूर्व या देरी से बोई गई फसल में कीट द्वारा अपेक्षाकृत अधिक क्षति होती है।

❖ चने की देशी प्रकार की किस्में जैसे जे.जी 315, जे.जी. 74 में गुलाबी (जेजीजी 1) तथा काबुली (जेजीके 1, काक-2) प्रकार की किस्मों की अपेक्षा कीट प्रकोप कम होता है। अत: ऐसे क्षेत्र जहां पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है वहां चने की देशी किस्मों का प्रयोग करें। यदि गुलाबी या काबुली किस्में लगा रहे हैं तो इस कीट के प्रकोप का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक नियंत्रण उपाय करें।

❖ शुद्ध चने की अपेक्षा चने के साथ 4:2 या 6:2 के अनुपात में सरसों या करडी या अलसी की फसल अंतरवर्तीय फसल पद्धति के रूप लगाने से चने पर इल्ली का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है।

❖ चने के खेत में मेढ़ों पर गेंदे की प्रपंची फसल लगाने पर इस कीट की मादा शंखी गेंदे पर अंडे देना अधिक पसंद करती है जिसे आसानी से रसायनिक कीटनाशकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार चने के खेत के चारों ओर धनिया की फसल एक सफल प्रपंची फसल सिद्ध हुई है। धनिया के फूल चने की इल्ली के परजीवी कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे खेत में परजीवी कीटों की संख्या

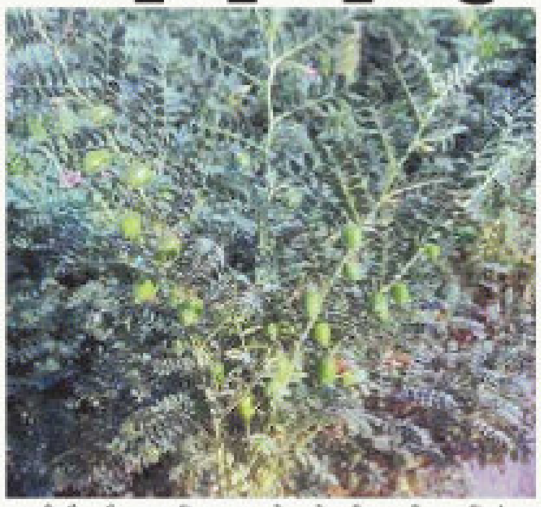

बढ़ती है और प्राकृतिक रूप से चने की इल्ली का नियंत्रण होता है।

❖ सोयाबीन-चना फसल चक्र में आमतौर पर यह देखा गया है कि चने के खेत में सोयाबीन के पौधे खरपतवार के रूप में उग आते हैं। यह पाया गया है कि चने की इल्ली चने के पौधों की अपेक्षा सोयाबीन के पौधों पर अपेक्षाकृत अधिक अंडे देती है। (सम्भवत: चौड़ी पत्ती होने के कारण)। अत: खरपतवार के रूप में उग आई सोयाबीन की निंदाई जनवरी माह के अंत तक करने से चने पर इल्ली संख्या नियंत्रित रहती है।

❖ फसल में उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने पर पौधों के ऊतक मुलायम हो जाते हैं। परिणामस्वरूप अधिक कीट प्रकोप होता है जबकि पोटाश की मात्रा पौधों के बाह्य ऊतकों को कड़ा बनाती है। जिससे कीटों द्वारा अपेक्षाकृत कम हानि होती है।

❖ यदि सिंचित चना लगा रहे हैं तो उपयुक्त समय पर सिंचाई करें। यह देखा गया है कि फली बनने के बाद सिंचाई करें तो इस कीट के प्रकोप के बढ़ने की आशंका होती है।

❖ इसी प्रकार फूल अवस्था आने पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर के आकार की खूंटियां, जो कि भूमि सतह से 3 मीटर ऊंची हों तथा दो खूंटियों के मध्य 4-5 मीटर का फासला हो, लगाना चाहिए। इन खूंटियों पर परभक्षी पक्षी बैठकर पौधों में लगी इल्लियों को खाकर नष्ट करते हैं। साधारणत: यह पाया गया है कि इल्ली परजीवी केम्पोसेटिस क्लोरिडी एवं परभक्षी पक्षी 85 प्रतिशत तक इल्ली संख्या नियंत्रित कर लेते हैं। फसल में दाना पकने की अवस्था आने पर इन खूंटियों को निकालना न भूलें, क्योंकि इस अवस्था में इल्ली संख्या कम हो जाती है और परभक्षी पक्षी इल्ली के न मिलने पर दानों को खाकर भी हानि कर सकते हैं।

❖ फूल एवं फली अवस्था पर खड़ी फसल की नियमित निगरानी अवश्य करें. फली अवस्था पर यदि प्रति मीटर कतार या प्रति दस पौधों पर पाई जाने वाली औसत संख्या 1-1.5 सुण्डी मिलने लगे तो रसायनिक नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए।

❖ कीटनाशकों के छिड़काव करने की स्थिति आने पर प्रथम छिड़काव फूल एवं फली आने की अवस्था में न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस विषाणु (एन.पी.व्ही.) का 250 इल्ली तुल्य छिड़कें। छिड़काव सायंकाल में करना प्रभावी होता है। एन.पी.व्ही. के घोल में (5 मि.ली./लीटर पानी की दर से तैयार) एक प्रतिशत टीपॉल मिलायें। यह रसायन विषाणु की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें विषाणु का प्रभाव नष्ट कर देती हैं। इस घोल में वयस्क शंखियों को आकर्षित करने के लिये 0.5 प्रतिशत गुड़ मिलाना प्रभावी होता है।

द्वितीय छिड़काव की आवश्यकता होने पर नीम आधारित वानस्पतिक कीटनाशक या उसके व्यवसायिक उत्पाद जैसे- अचूक, नीम गोल्ड, नीमार्क, निम्बेसिडिन, नीम गार्ड आदि का प्रयोग इल्ली के लिये प्रतिकूल तथा परजीवी कीटों और वातावरण के लिये सुरक्षित होता है। निम्बोली के सत का 5 प्रतिशत घोल इल्ली को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावशाली पाया गया है तथा यह एक सस्ता तथा सुरक्षित उपाय है। निम्बोली से सत निकालने के लिये सूखी निम्बोलियों को ओखली में खूब बारीक कूट लें और एक कपड़े में पोटली बनाकर शाम को पानी में भिगो दें। सुबह पोटली को दबाकर सफेद दूधिया रस निकालकर शेष पदार्थ को फेंक दें। उपलब्ध घोल में 1 प्रतिशत साबुन चूरा या डिटरजेंट पाउडर मिलाकर प्रति लीटर पानी में 5 मि.ली. नीम सत का घोल बनाकर छिड़काव करने से चने की इल्ली का प्रभावी नियंत्रण होता है।

यदि रसायनिक कीटनाशक का उपयोग आवश्यक हो तो इण्डोसल्फान 35 ई.सी. दवा की एक लीटर मात्रा या क्विनालफॉस 25 ई.सी. दवा की एक लीटर मात्रा या प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टर की दर से छिड़कें। असिंचित चने में पानी की मात्रा प्रति हेक्टर 500 लीटर तथा सिंचित फसल में पानी की मात्रा 750 लीटर प्रति हेक्टर रखें. उपरोक्त रसायनों में से किसी एक का छिड़काव यंत्र की सहायता से छिड़कें। यदि घोल बनाने के लिये पानी की उपलब्धता न हो तो कीटनाशी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिये फेनवेलरेट 0.4 प्रतिशत चूर्ण या मिथाईल पैराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण या इण्डोसल्फान 4 प्रतिशत चूर्ण में से किसी एक चूर्ण का 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव यंत्र की सहायता से भुरकाव करें।

अधिक प्रकोप होने की स्थिति में प्रोफेनोफॉस तथा सायपरमेथ्रिन 44 ई.सी. कीटनाशक मिश्रण की एक लीटर मात्रा प्रति हेक्टर की दर से छिड़कें।

सावधानी

रसायनिक कीटनाशक जहरीले होते हैं अत: पर्याप्त सावधानी तथा सुरक्षा अपनाते हुए इनका उपयोग करें। ध्यान रहे चने की इल्ली की छोटी अवस्था में ही उसका नियंत्रण करना आसान तथा लाभदायक होता है। जब इल्ली अधिक संख्या में होती है और बड़ी अवस्था में आती है तभी कृषकों का ध्यान उसके नियंत्रण की ओर जाता है। बड़ी अवस्था की इल्ली का नियंत्रण अपेक्षाकृत दुष्कर कार्य है क्योंकि इस अवस्था की इल्ली में छोटी इल्ली की अपेक्षा कीटनाशी प्रतिरोधकता अधिक होती है तथा मरने के पूर्व वह फसल में काफी हानि कर चुकी होती है। अत: नियमित फसल निगरानी आवश्यक है।

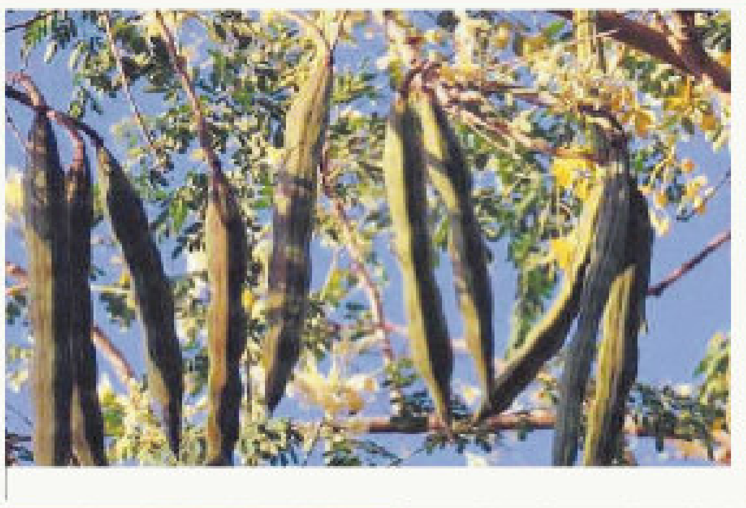

सदाबहार सुरजना (मुनगा) लगायें

प्रकृति का चमत्कार ही है कि उसने सहजन या सुरजना की फली के वृक्ष को इतनी विशेषताएं प्रदान की हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्राकृतिक जैव विविधता को पहचाने और उसके संवर्द्धन की दिशा में उचित प्रायस करें।

हमारी हवा, पानी, मिट्टी अब आगे और खराब न हों, खेतों की मिट्टी अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहे यह आज की एक गंभीर समस्या है। मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिये रासायनिक खाद व कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का कम उपयोग करना होगा। जैविक खेती पर ज्यादा जोर देना होगा। कोशिश करना होगी कि खेती पर ऊर्जा की निर्भरता कम हो। किसानों को भी अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्यरक्षक ईंधन उपलब्ध हो। पशुओं को बढ़िया पौष्टिक चारा मिले और किसानों को आर्थिक आजादी हो, परंतु ये सब होगा कैसे? वर्तमान अंधकारमय परिदृश्य में आशा कि एक किरण नजर आती है। यह सब संभव है।

केवल एक पेड़ के समुचित प्रबंध से इसका नाम है सहजन जिसे हम सुरजने के नाम से जानते हैं। मुनगा भी यही है और मोरिंग भी. इसकी लम्बी ड्रमस्टिक के नाम से जानी जाने वाली फलियों को सब्जी के रूप में सदियों से उपयोग में ला रहे हैं। परंतु इसके अन्य अद्‌भुत गुणों से अनजान हैं। यह पूरा पेड़ बड़ा चमत्कारी है। इससे देश के किसान विशष कर छोटे किसानों की किस्मत का ताला खुल सकता है।

सुरजने की पत्तियां और टहनियां पशुओं के लिये पौष्टिक चारा है। बीज बोने के पूर्व यदि सुरजने की पत्तियों को खेत में मिलाएं तो उससे जड़ों में लगने वाले सड़न और गलन रोग से मुक्ति मिलती है।

इसकी पत्तियों का रस फसलों के लिये बेहतर टॉनिक का काम करता है। इसकी पत्तियों के रस के छिड़काव से फसलों का उत्पादन 30 प्रतिशत तक बढ़ता है। इसके पौधों को खेत में हरी खाद के साथ में मिलाया जा सकता है। यह प्राकृतिक खाद का काम करता है। सुरजने की पत्तियों से प्रदूषण रहित स्वच्छ बायो गैस बनाई जा सकती है। इसका उपयोग मिश्रित खेती में भी किया जा सकता है। क्योंकि इस पेड़ से छाया नहीं होती और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन युक्त जीवांश मिलता है। इसके बीजों के चूर्ण को शहद साफ करने के काम में लाया जाता है। गन्ने के रस को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।

इस पर फूलों की बड़ी बहार आती है, जिसमें मकरन्द अधिक मात्रा में होता है। अत: इसका उपयोग शहद उत्पादन में भी होता है। बीजों से खाद्य तेल निकलता है, जो गुणवत्ता में ओलिव ऑयल (अलसी का तेल) के समान है। बीजों में 40 प्रतिशत तक तेल पाया गया है। बीजों के चूर्ण का उपयोग गंदे पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। यह फिटकरी के मुकाबले पानी को ज्यादा साफ करता है। साथ ही बैक्टीरिया को हटाता है। मलावी और अफ्रीका में इसके बीजों से बड़े पैमाने पर पानी साफ किया जा रहा है। यही नहीं इसके बीजों से पानी का ठोसपन भी कम होता है।

इनके अलावा इसका गूदा अखबारी कागज बनाने के काम भी लाया जा सकता है। छाल से रस्सियां बनाने के लिये उम्दा किस्म का रेशा प्राप्त होता है।

फलियां बेचकर आर्थिक आय तो प्राप्त की ही जा सकती है। इसकी पत्तियां, फूल, फल, बीज ओर तो ओर छाल सभी कुछ उपयोगी है. इसके इन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर इसे मूरे में अरजन टिंगा कहा जाता है। जिसका अर्थ है स्वर्ग का पेड़। तो अब स्वर्ग के इस पेड़ को खेतों की मेड़ों पर, सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर लगाया जा सकता है और साथ ही हम पा सकते हैं उत्तम स्वास्थ्य, बढ़िया पशुधन ढेर सारा पैसा और बोनस के रूप में स्वच्छ पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास।

कद्दूवर्गीय सब्जियां और कीट- बीमारियां

हमारे देश में मुख्य रूप से लौकी, करेला, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, घीया, टिण्डा, परवल को ग्रीष्म व वर्षाऋतु में उगाते हैं. इन सब्जियों पर रोग व कीड़ों के आक्रमण से काफी नुकसान होता है यदि इन व्याधियों को समय पर नियंत्रित कर दिया जाये तो उत्पादन को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. कद्दूवर्गीय सब्जियों में लगने वाले प्रमुख रोग कीट व उनका नियंत्रण इस प्रकार किया जा सकता है.

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट

कद्दू का लाल गिडार

लाल रंग का उड़ने वाला यह कीट शिशु पौधों की पत्तियों को खाकर छलनी जैसे छिद्र कर देता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है फलों में भी यह छेदकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है कीट नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. या ऐसीफेट 75 एस.पी. के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए.

फलवेधक मक्खी

कीट का मैगट फलों एवं बेलों को खाते हैं जिससे बेल में गांठे बन जाती हैं. मादा मक्खी अपने अंडरोपक की सहायता से फलों की ऊपरी सतह में छिद्र करने के पश्चात अंडरोपण करती है जिससे वहां फल की सतह के ऊपर रस जमकर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है और अंत में फल सड़ जाते हैं. कीट नियंत्रण हेतु मैलाथियान या डाइमिथियेट 30 ई.सी. का 0.1 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करना चाहिए.

माहू

इस कीट के शिशु व वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर करते हैं साथ ही विशेष प्रकार का मधुस्राव पत्तियों पर छोड़ते हैं जिस पर बाद में फफूंद लग जाने से वह स्थान काला रंग का हो जाता है. यह कीट मोजेक रोग को रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक फैलाते हैं नियंत्रण हेतु ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 25 ई.सी. अथवा डाइमिथियेट 30 ई.सी. 1.0 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिये.

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग

चूर्णीफफूंद या भभूतिया रोग- इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से खीरा, लौकी, खरबूज में होता है. रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की निचली सतह पर गोल-गोल सफेद धब्बे बनते हैं तथा रोग के उग्र होने पर ये धब्बे भूरे हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण बिखरा रहता है, बाद में पत्तियां सड़ जाती हैं आर्द्र व ऊष्ण जलवायु में यह रोग अधिक लगता है रोग नियंत्रण हेतु कवकनाशी-केराथेन 0.5 प्रतिशत अथवा सल्फेक्स 0.2 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए.

मृदुरोमिल आसिता

लौकी, खीरा, खरबूज, करेला आदि में सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले धब्बे बनते हैं तथा निचली सतह पर रुई जैसी वृद्धि दिखाई देती है. रोग नियंत्रण हेतु 0.3 प्रतिशत का छिड़काव 10 दिन के अंतर से करना चाहिए.

आल्टरनेरिया झुलसन रोग

आल्टरनेरिया झुलसा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर छोटे-छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में संख्या व आकार में बढ़कर मिलकर पूरी पत्ती को झुलसा देते हैं. नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 0.3 प्रतिशत अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए.

मोजेक

विषाणुजनित इस रोग मे पत्तियों पर पीलापन, सिकुड़न, इंटरनोड का छोटा होना प्रदर्शित होता है इस रोग का संचरण माहू नामक कीट द्वारा होता है रोग से बचाव हेतु वाहक कीट का नियंत्रण आवश्यक है. अत : ऑक्सी मिथाइल डिमेटान 25 ई.सी. या डाईमिथियेट 30 ई.सी. 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करें. प्रारंभिक अवस्था में रोगित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए.

कलिंग समाचार

संपादकीय

राहुल गांधी से भाजपा की चिढ़ का कारण

राहुल गांधी से भाजपा की नफरत क्यों करती है, क्यों उनके हर काम से, हर कदम से भाजपा को आपत्ति होती है, इसका एक बड़ा कारण शनिवार को सामने आया, जब राहुल ज मू-कश्मीर के पुंछ पहुंच गए। जिस समय राहुल पुंछ में पाक की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिल रहे थे, उजड़े हुए घरों को देख रहे थे, बेरौनक आंखों में भरे हुए दर्द को समझने और बांटने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को हि मत बंधा रहे थे कि उनका दुख अनसुना नहीं रहेगा, वो राष्ट्रीय स्तर तक उनकी आवाज़ उठाएंगे, प्रधानमंत्री के सामने उनकी पीड़ा को बयां करेंगे, उस समय श्री मोदी राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक ले रहे थे, जिसमें 2047 के विकसित भारत का रोडमैप बनाने की बातें हो रही थीं। राहुल गांधी से भाजपा की चिढ़ का कारण राहुल गांधी से भाजपा की नफरत क्यों करती है, क्यों उनके हर काम से, हर कदम से भाजपा को आपत्ति होती है, इसका एक बड़ा कारण शनिवार को सामने आया, जब राहुल ज मू-कश्मीर के पुंछ पहुंच गए। जिस समय राहुल पुंछ में पाक की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिल रहे थे, उजड़े हुए घरों को देख रहे थे, बेरौनक आंखों में भरे हुए दर्द को समझने और बांटने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को हि मत बंधा रहे थे कि उनका दुख अनसुना नहीं रहेगा, वो राष्ट्रीय स्तर तक उनकी आवाज़ उठाएंगे, प्रधानमंत्री के सामने उनकी पीड़ा को बयां करेंगे, उस समय श्री मोदी राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक ले रहे थे, जिसमें 2047 के विकसित भारत का रोडमैप बनाने की बातें हो रही थीं। फर्क जाहिर है राहुल गांधी आज 2025 के भारत में जो कुछ हो रहा है इसकी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन श्री मोदी आज से 25 साल बाद के भारत की बात कर रहे हैं। मान लिया कि अच्छे राजनेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पास की चीजें नजर ही न आएं। 2047 में भारत कैसा रहेगा, इसकी तैयारी अभी के हाल पर निर्भर करती है। और अभी का हाल ऐसा है कि नरेन्द्र मोदी जैसे कभी मणिपुर नहीं गए, वैसे ही उन्होंने ज मू-कश्मीर जाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तमाम राज्यों में हो आए हैं। जबकि राहुल गांधी पहलगाम हमले के फौरन बाद अपनी विदेश यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आए, श्रीनगर गए, इसके बाद कानपुर और करनाल जाकर भी पीड़ित परिवारों से मिले। राहुल गांधी ने शुरु से पहलगाम हमले को लेकर काफी संयम, समझदारी और संवेदनशीलता दिखाई है। जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि सरकार जो चाहे फैसला ले, हम साथ हैं। सरकार की तरफ से दो बार बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी राहुल शामिल हुए, जबकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने इन बैठकों से दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल नहीं किए, बस उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी, ताकि दुनिया को मजबूती का संदेश दिया जा सके। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सेना के शौर्य की सराहना की। मगर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इसी कोशिश में लगे रहे कि कैसे भी करके इसका सियासी फायदा लिया जाए। धर्म पूछा जाति नहीं जैसी पोस्ट भाजपा ने सोशल मीडिया पर डाली, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्यवर्दी में नरेन्द्र मोदी का आदमकद पोस्टर लगाया गया, मानो वही लड़ाकू विमान लेकर पाकिस्तान तक गए थे। इतना सब काफी नहीं था, जो अब नरेन्द्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को भी अपनी निजी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। राजस्थान में उनका दिया भाषण इसका सबूत है, जिसमें उन्होंने मेरी रगों में लहू नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है जैसा घटिया फिल्मी संवाद कहा। देश ने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, जो अपनी शारीरिक संरचना को लेकर भी बार-बार बयान बदल सकता है। एक साल पहले तक श्री मोदी कह रहे थे मैं नॉनबायलॉजिकल हूं, अब अपनी रगों में गर्म सिंदूर बहने का दावा उन्होंने किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता की जिमेदारी पोप पर डाली

टी एन अशोक

बहुप्रतीक्षित ट्रंप-पुतिन कॉल से पहले, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने कहा कि उन्होंने रविवार को ट्रंप से बात की। ब्रिटिश सरकार ने एक बयान में कहा कि वह %पुतिन से शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का आग्रह कर रही है।% बयान में कहा गया है कि उन नेताओं ने %रूस द्वारा युद्धविराम और शांति वार्ता में गंभीरता से शामिल न होने पर प्रतिबंधों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की-

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र प ने यूक्रेन और रूस के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपने शांति प्रयासों को लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि सोमवार को तथाकथित दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दो घंटे की बातचीत नो एंट्री ज़ोन में समाप्त हो गयी। वेटिकन अब रूसी और यूक्रेनी नेताओं के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने के लिए दृश्य में प्रवेश कर गया है।

कोई नहीं जानता कि राष्ट्रपति ट्र प ने शिकागो में जन्मे पोप लियो-14 से मदद मांगी या नहीं, ताकि वे उन्हें बचा सकें और वार्ता की मेजबानी कर सकें, ताकि दोनों नेता उनकी बात सुन सकें। लेकिन वीपी जेडी वांस ने वास्तव में शिकागो के नये पोप लियो-14 से मुलाकात की और यूक्रेन सहित वैश्विक स्थिति के बारे में बताया।

ट्र प ने यूक्रेन में युद्ध के रक्तपात को रोकने के प्रयास में सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अन्य नेताओं से अलग-अलग कॉल में बात की। लेकिन राष्ट्रपति की शांति पहल अनिर्णायक रही, जिससे वे निराश हो गये। ट्र प ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि-रूस और यूक्रेन अब %तुरंत% युद्ध विराम पर सीधी बातचीत करेंगे।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि ये वार्ता किस रूप में होगी या कब होगी। ट्र प ने कहा कि वेटिकन ने वार्ता की मेजबानी करने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा, %इसके लिए शर्तें दोनों पक्षों के बीच बातचीत से तय होंगी, क्योंकि ऐसा केवल इसलिए हो सकता है, क्योंकि वे वार्ता के विवरण जानते हैं, जिसके बारे में किसी और को पता नहीं होगा।% पुतिन के साथ ट्र प की कॉल दो घंटे से अधिक समय तक चली और %बहुत जानकारीपूर्ण और बहुत खुली थी,% पुतिन ने रूसी राज्य मीडिया को बताया। ट्र प ने ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के बारे में बहुत कम कहा, जिनसे उन्होंने सबसे पहले बात की, सिवा इसके कि उन्होंने ज़ेलेंस्की और अन्य नाटो देशों के नेताओं को वार्ता के बारे में सूचित कर दिया था। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को ज़ेलेंस्की से दो बार बात की, एक बार आमने-सामने, पुतिन के साथ ट्रंप की कॉल से पहले, और फिर यूक्रेनी और नाटो नेताओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान।

ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से फिर से कहा कि-यूक्रेन पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम के लिए तैयार है।% उन्होंने लिखा, %अगर रूसी हत्याओं को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन पर कड़े प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए। %रूस पर दबाव उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा - यह दुनिया भर में सभी के लिए स्पष्ट है, रोम में एनबीसी न्यूज के साथ सोमवार को एक साक्षात्कार में, जहां पोप लियो-14 ने उनका स्वागत किया, उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा, यह जोड़ते हुए कि %हमने पोप के साथ राष्ट्रपति की प्रमुख शांति पहलों के बारे में बात की। हमने इस बारे में बहुत बात की कि इज़राइल और गाजा में क्या चल रहा है। हमने रूस-यूक्रेन की स्थिति के बारे में बहुत बात की। भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि, न केवल पोप, बल्कि पूरे वेटिकन ने, आप जानते हैं, वास्तव में मददगार होने की इच्छा व्यक्त की है, और उ मीद है कि एक शांति समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करना है। भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह बहुत सार्थक था, और मुझे उ मीद है कि देश के लिए इसका फल मिलेगा। इस बीच, पुतिन के प्रवक्ता दिमित्रिपेसकोव ने कॉल से पहले कहा कि रूस %अमेरिका को बहुत महत्व देता है% और %अमेरिकी पक्ष का आभारी है।% पत्रकारों के साथ एक ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका %शांतिपूर्ण तरीकों से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, तो यह वास्तव में बेहतर है।% पेसकोव से ट्रंप और पुतिन की व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की संभावना के बारे में भी पूछा गया, जिसकी संभावना अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को जताई थी। पेसकोव ने कहा, %यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वे खुद क्या फैसला करते हैं।% उन्होंने कहा कि तारीखों और अन्य विवरणों के संदर्भ में दोनों नेताओं द्वारा बैठक पर %काम करने की जरूरत है%।

बहुप्रतीक्षित ट्रंप-पुतिन कॉल से पहले, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने कहा कि उन्होंने रविवार को ट्रंप से बात की। ब्रिटिश सरकार ने एक बयान में कहा कि वह पुतिन से शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का आग्रह कर रही है। बयान में कहा गया है कि उन नेताओं ने रूस द्वारा युद्धविराम और शांति वार्ता में गंभीरता से शामिल न होने पर प्रतिबंधों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की- कुछ ऐसा जिसकी ट्रंप पहले भी धमकी दे चुके हैं। फरवरी 2022 में शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए कई दौर की शांति वार्ताएं हो चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सभी कब्जे वाली भूमि को रूसी के रूप में मान्यता देने, रूस को वे सभी क्षेत्र दिये जाने की मांग कर रहे हैं जिन पर उसका दावा है लेकिन उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

बहुप्रतीक्षित ट्रंप-पुतिन कॉल से पहले, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने कहा कि उन्होंने रविवार को ट्रंप से बात की। ब्रिटिश सरकार ने एक बयान में कहा कि वह %पुतिन से शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का आग्रह कर रही है।% बयान में कहा गया है कि उन नेताओं ने %रूस द्वारा युद्धविराम और शांति वार्ता में गंभीरता से शामिल न होने पर प्रतिबंधों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की%- कुछ ऐसा जिसकी ट्रंप पहले भी धमकी दे चुके हैं। फरवरी 2022 में शुरू होने के बाद से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए कई दौर की शांति वार्ताएं हो चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सभी कब्जे वाली भूमि को रूसी के रूप में मान्यता देने, रूस को वे सभी क्षेत्र दिये जाने की मांग कर रहे हैं जिन पर उसका दावा है लेकिन उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। फिर यह गारंटी भी कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, और वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों की पूरी तरह वापसी, कैदियों और अपहृत यूक्रेनी बच्चों की वापसी, युद्ध अपराधों के लिए रूसी नेताओं पर मुकदमा चलाने और आगे रूसी आक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच पहली बैठक आक्रमण शुरू होने के चार दिन बाद, 28 फरवरी 2022 को बेलारूस में हुई और बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई। बाद में वार्ता के दौर हुए-मार्च 2022 में बेलारूस-यूक्रेन सीमा पर और तुर्की के अंताल्या में। तुर्की में बातचीत से एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यूक्रेन नाटो में शामिल होने की योजना को छोड़ देगा और अपनी सेना पर सीमाएं लगायेगा, जबकि पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी होगी और रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करने को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं होगी। मसौदा संधि पर लगभग सहमति बन गयी थी, लेकिन सुरक्षा गारंटी और बुचा नरसंहार पर असहमति ने अंततः वार्ता की सफलता को रोक दिया।

डोनाल्ड ट्र प के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद 2025 में नये सिरे से बातचीत शुरू हुई। ट्र प ने इस साल 12 फरवरी को पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की और उसके तुरंत बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात की। सऊदी अरब शांति वार्ता के लिए प्राथमिक मेज़बान देश के रूप में उभरा। अमेरिका-रूस शिखर स मेलन के बाद, ट्र प और ज़ेलेंस्की के बीच संबंध खराब हो गये, जिसकी परिणति 28 फ़रवरी को दोनों के बीच हुई बैठक में हुई जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेनियों को बीच में ही चले जाने के लिए कहा और एक नियोजित यूक्रेन-अमेरिका खनिज राजस्व सौदे को छोड़ दिया। बैठक के बाद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने यूक्रेन में सैनिकों के साथ %इच्छुक गठबंधन% द्वारा संरक्षित युद्ध विराम की योजना बनायी। मार्च से रूस और यूक्रेन दोनों द्वारा कभी-कभी कुछ सीमित युद्ध विराम पर सहमति होती रही है।

तमिलनाडु में बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन

डॉ. ज्ञान पाठक

तमिलनाडु में दो भाषा नीति है- तमिल और अंग्रेजी। 1968 से ही यह लगातार हिंदी थोपने का विरोध करता रहा है, जब राज्य की विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 में कक्षा 1 से 10 तक तमिल की शिक्षा अनिवार्य है। तमिलनाडु यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 नामक एक और अधिनियम है।

तमिलनाडु के बच्चे केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और राज्य में सीएम एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार के बीच राजनीतिक टकराव में फंस गये हैं। केंद्र नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने पर जोर दे रहा है, और राज्य इसे लागू करने से इंकार कर रहा है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मई, 2025 को कहा था कि न्यायालय किसी भी राज्य को एनईपी अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर भी, तीन-भाषा फार्मूले के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए, केंद्र ने धन जारी करने पर रोक लगा दी है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश में देरी हो रही है। अब, तमिलनाडु ने 2,151 करोड़ रुपये के शिक्षा कोष को रोक रखने के मामले में केंद्र के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार पर एनईपी 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना से केन्द्रीय आवंटन जारी करने को जोड़कर संघीय अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। राज्य द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है, %इस तरह की जबरदस्ती की रणनीति न तो कानूनी रूप से स्वीकार्य है और न ही राज्य के कानून के अनुरूप है, खासकर राज्य द्वारा अपनाये गये दो-भाषा फार्मूले के आलोक में।

तमिलनाडु ने 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा योजना (एसएसए) के तहत शिक्षा कोष में 2151 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है, और साथ में मूल राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज की भी। इस प्रकार मुकदमे का कुल दावा 2291.3 करोड़ रुपये है।

तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा है कि एसएसए के तहत केंद्र द्वारा अपने %अनिवार्य हिस्से% को रोके रखने से बच्चों को मु त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन बाधित हुआ है और राज्य में 43.94 लाख से अधिक छात्रों, 2.21 लाख शिक्षकों और 32,701 स्कूल कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।

तमिलनाडु का कहना है कि भारत संघ के शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने फरवरी 2024 की बैठक में एसएसएस के तहत राज्य के लिए 3,585.99 करोड़ रुपये मंजूर किये थे, जिसमें से 2,151.59 करोड़ रुपये 60:40 लागत-साझाकरण फॉर्मूले के आधार पर केंद्र का हिस्सा था। फिर भी, केंद्र ने एक भी किस्त जारी नहीं की है। राज्य ने आरोप लगाया कि केंद्र ने ऐसा राज्य द्वारा एनईपी 2020 को पूरी तरह से अपनाने और पीएम श्री स्कूल योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने के कारण किया है।

तमिलनाडु में दो भाषा नीति है- तमिल और अंग्रेजी। 1968 से ही यह लगातार हिंदी थोपने का विरोध करता रहा है, जब राज्य की विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 में कक्षा 1 से 10 तक तमिल की शिक्षा अनिवार्य है। तमिलनाडु यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 नामक एक और अधिनियम है।

फिर भी, केंद्र द्वारा एनईपी-2020 को लागू करने के लिए इन कानूनों को कमजोर किया जा रहा है, जो केवल एक नीति और विजन स्टेटमेंट है... जिसमें राज्य पर बाध्यकारी कोई कार्यकारी या विधायी बल नहीं है।

तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों को समग्र शिक्षा योजना के तहत धन जारी किया है।

9 मई, 2025 को ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनईपी 2020 को लागू करने के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था, यह कहते हुए कि अदालत किसी भी राज्य को इसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश आर महादेवन की पीठ ने कहा कि, वे तभी हस्तक्षेप करेंगे जब एनईपी 2020 से संबंधित किसी राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। जनहित याचिका तमिलनाडु के एक वकील और भाजपा नेता ने दायर की थी।

कुछ दिन पहले ही 16 मई को तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से एसएसएस के तहत 2151.59 करोड़ रुपये की लंबित बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया था, जिसमें आरटीई प्रवेश के लिए 617 करोड़ रुपये भी शामिल थे।

राज्य में भाजपा की सहयोगी एआईएडीएम के पिछले दो वर्षों से निजी स्कूलों को आरटीई प्रतिपूर्ति निधि में देरी करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना कर रही है, जिसके कारण इस शैक्षणिक वर्ष में आरटीई प्रवेश में देरी हुई है।

राज्य सरकार ने परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी सौंपा है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र द्वारा 2,733.58 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गयी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2151.59 करोड़ रुपये होगा। तमिलनाडु ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त जारी करने के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए पूरी अनुमोदित धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 मई, 2025 को तमिलनाडु सरकार को निजी स्कूलों में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश शुरू करने में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था।

ध्यान रहे कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होती है।

मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गयी मरुमलार्चीमक्कलइयक्कम के अध्यक्ष वी ईश्वरन की याचिका में कहा गया है कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आम तौर पर हर साल 20 मई तक समाप्त हो जाती है। तमिलनाडु के सभी स्कूल 2 जून को फिर से खुलने वाले हैं।

हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने कानून के अनुसार लाखों गरीब बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपनी जि मेदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा है कि केंद्र ने तमिलनाडु को शिक्षा के लिए रोके गये फंड को जारी करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, %केंद्र को आरटीई फंड जारी करना होगा। ... फंड जारी न करना मानवाधिकारों के खिलाफ काम करने जैसा है।

विविध समाचार

हिमाचल में 2 दशक बाद आया भूकंप का इतना बड़ा झटका, 3 बार हिली धरतीय अस्पताल और कई घर क्षतिग्रस्त

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बीती रात कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां एक के बाद एक आए भूकंप के तीन जोरदार झटकों ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। रातभर धरती हिलने के कारण लोग बेहद दहशत में रहे और खौफ के मारे पूरी रात सो नहीं पाए। पहला और सबसे तेज झटका रात 10:04 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई। इसके बाद भी धरती शांत नहीं हुई और रात 11:04 बजे 2.8 तीव्रता तथा ठीक 11:52 बजे 3.0 तीव्रता के दो और झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस आपदा के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इन तीनों ही भूकंपों का केंद्र हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला रहा। पहला झटका इतना तीव्र और खतरनाक था कि लोग घबराकर अपने घरों और बहुमंजिला इमारतों से बाहर खुली सड़कों की तरफ दौड़ पड़े। भूकंप का असर सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तेज कंपन पड़ोसी राज्य पंजाब में भी साफ तौर पर महसूस किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भूकंप जमीन की बेहद कम गहराई में आया था, यही वजह है कि 5.0 तीव्रता के इस झटके का प्रभाव प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में इतना जोरदार और विनाशकारी रहा। इस भूकंप के कारण जिला कांगड़ा के धर्मशाला में कई घरों की दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं। वहीं, पालमपुर के सिविल अस्पताल से एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रात को आए पहले झटके के कारण अस्पताल के पुराने भवन की दूसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में सभी मरीज पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना के बाद वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों में चीख–पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस भवन को काफी समय पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था, इसके बावजूद वहां मरीजों का इलाज चल रहा था जो एक बड़े हादसे को दावत दे रहा था। भूकंप की इस त्रासदी ने कई गरीब परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माहड़ गांव में जिगरी राम नाम के एक ग्रामीण का स्लेटपोश मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान की छत पूरी तरह ढह गई है, जिससे वह अब रहने लायक नहीं बचा है। बेघर हुए पीड़ित परिवार ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी और अब सरकार तथा जिला प्रशासन से तत्काल आर्थिक राहत और मदद की गुहार लगाई है। भू–वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दो दशकों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए अधिकांश भूकंपों की तीव्रता दो से चार रिक्टर स्केल के बीच ही दर्ज की गई है, जिन्हें हल्के झटके माना जाता है।

सीएम मान के ऐलान के बाद निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के आदेश

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा के 24 घंटों से भी कम समय में पंजाब सरकार ने इस निर्णय को कानून का रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तुरंत कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निजी स्कूलों की फीस को नियमित किया जा सके और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इससे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें। अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, "सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।" शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, "नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।" प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी। भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

गर्मियों की छुट्टियों के चलते मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट रहेगी बंद

जालंधर। गर्मियों की छुट्टियों को लेकर मॉडल टाउन मोबाइल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार दुग्गल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट के सभी प्रमुख दुकानदारों एवं व्यापारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मॉडल टाउन मोबाइल एसोसिएशन से संबद्ध सभी मोबाइल फोन, मोबाइल एक्सेसरीज तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठान 25 जून से 28 जून 2026 तक बंद रहेंगे। इस दौरान पूरी मोबाइल मार्केट में व्यावसायिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार दुग्गल ने बताया कि यह फैसला सभी दुकानदारों की सहमति से लिया गया है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि वे मोबाइल खरीदने, मरम्मत करवाने अथवा अन्य आवश्यक कार्यों की योजना पहले से बना लें, ताकि अवकाश अवधि के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में विक्की जुनेजा, प्रिंस जुनेजा, मोंटू जुनेजा, मोहित हंस, गगन वड्डू, आकाश बजाज, सरबजीत सिंह, विशाल तथा माधव शूर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

स्वातंत्र्य समर के अमर पुरोधा भगवान बिरसा मुंडा और सनातन वनवासी चेतना

इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय इतिहास की मुख्यधारा ने सदैव वनवासी समाज को शेष राष्ट्र से पृथक करके देखने का प्रयास किया है, किंतु प्राचीन भारतीय वांग्मय का समीचीन अध्ययन इस औपनिवेशिक नैरेटिव का पूर्णतः खंडन करती है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने एक छद्म नैरेटिव गढ़ा कि भारत का वनवासी समाज मुख्यधारा से पृथक, आदिम और असभ्य था, किंतु इस ऐतिहासिक मिथक का खंडन संसार के सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद 10146 का अरण्यानी सूक्तस्वतः कर देता है, जहां वनों को केवल काष्ठ का संचय नहीं, अपितु जीवनदायिनी, अमूर्त और परम पूजनीय सत्ता माना गया है।उल्लेखनीय है कि वैदिक काल से ही भारतीय मनीषा ने वनों और वनवासियों को राष्ट्र की सांस्कृतिक संप्रभुता का रक्षक माना है। ऋग्वेद काअरण्यानी सूक्तवन को एक जीवंत, पूजनीय और स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करता है–

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।
कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती।।
–ऋग्वेद 10/146/1

यह सूक्त सिद्ध करता है कि वनवासी समाज कभी भी मुख्यधारा से कटा हुआ नहीं था, बल्कि वह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर राष्ट्र का पोषण करता था।अरण्यानी सूक्त में अंकित मंत्र सिद्ध करते हैं कि वन और वनवासी वैदिक काल से ही राष्ट्र की आर्थिकी, आध्यात्मी और रक्षातंत्र के अभिन्न अंग थे। महाभारत के उद्योगपर्व एवं सभापर्वमें सहदेव की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में जिन अटविक राजाओंका वर्णन आता है, वे संप्रभु थे, किंतु भारतवर्ष की केंद्रीय सांस्कृतिक सत्ता के प्रति निष्ठावान थे।अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए किसी भी साम्राज्य के समक्ष नतमस्तक नहीं होते थे। रामायण काल में भगवान श्रीराम का निषादराज गुह और शबरी से मिलन इसी एकात्मता का प्रतीक है।

भारतीय परंपरानुसार इतिहास की गतिशीलता जब–जब जड़ता को प्राप्त होती है, तब–तब इतिहासपुरुषों का प्राकट्य युगीन क्रांतियों को जन्म देता है। सनातन वनवासी चेतना जगाने वाले वीर बिरसा मुंडा भी ऐसे ही प्रकटित महापुरुष थे, जो मात्र एक युगीन क्रांति के प्रणेता नहीं थे, अपितु वे उस शाश्वत सनातन चेतना के आधुनिक विग्रह थे, जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में समाहित हैं।बिरसा मुंडा के प्राप्य जीवन वृत्त के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनका 26 वर्षीय लघु जीवनवृत्त मात्र एक विद्रोह की गाथा नहीं है, अपितु वह मध्यकाल से सुसुप्त पड़ी भारत की उस अटविक चेतनाका शंखनाद था, जिसका मूलाधार हमारे प्राचीनतम वांग्मय में सुरक्षित है।बिरसा मुंडा का उलगुलान (महाक्रांति) इसी प्राचीन, अक्षुण्ण वनवासी स्वाभिमान का आधुनिक संस्करण था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और ईसाई मिशनरियों ने जल, जंगल, जमीन के साथ–साथ वनवासियों की सनातन संस्कृति पर आघात किया, तब बिरसा मुंडा के रूप में उसी अटविक चेतनाने पुनः अंगड़ाई ली।जब 19वींशताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्टके माध्यम से वनवासियों को उनकी ही मातृभूमि से बेदखल करना प्रारंभ किया, और जब ईसाई मिशनरियों ने अकाल तथा विपन्नता का लाभ उठाकर उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठाराघात किया, तब इस औपनिवेशिक और मजहबी आक्रमण के विरुद्ध प्राचीन वैदिक क्षात्रतेज का जागरण अनिवार्य हो गया। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान (महाक्रांति) इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंकुरित हुआ। यह भूमि के टुकड़े के लिए किया गया तात्कालिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित ष्स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः के सिद्धांत की व्यावहारिक परिणति थी। बिरसा मुंडा ने यह अनुभव किया था कि भौतिक स्वतंत्रता तब तक असंभव है, जब तक समाज वैचारिक और आत्मिक रूप से दास बना रहेगा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जब छोटानागपुर क्षेत्र में जनजातीय समाज अपनी जड़ों से विमुख हो रहा था, तब भगवान बिरसा ने केवल अस्त्र नहीं उठाए, अपितु एक वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया, जिसे बिरसायत पंथकहा गया।यह कोई नवीन धार्मिक संप्रदाय नहीं, बल्कि विकृतियों को दूर कर सनातन जीवन पद्धति को पुनः अपनाने का एक अभिनव प्रयास था।यह उपनिषदों के एकेश्वरवाद और श्रीमद्भगवद्गीता के निष्काम कर्मयोग का ही व्यावहारिक रूप था।एकेश्वरवाद की पुनर्स्थापना करते हुए उन्होंने सिंगबोंगा (एक ईश्वर) की आराधना पर बल दिया, जो छान्दोग्य उपनिषद के एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मके दर्शन के समतुल्य है।उन्होंने अनेक काल्पनिक भयों और क्षुद्र शक्तियों की पूजा का निषेध कर सिंगबोंगा(एकमात्र परमेश्वर) की उपासना का निर्देश दिया। यह दर्शन छान्दोग्य उपनिषद के अद्वैत चिंतन का ही सहज जनजातीय रूपांतरण था।सांस्कृतिक शुचिता स्थापित करने के लिए उन्होंने मद्यपान, पशुबलि और अंधविश्वासों का निषेध कर यज्ञोपवीत धारण करने तथा शाकाहार अपनाने, तुलसी की उपासना करने की प्रेरणा दी। यह सनातन धर्म के यम–नियम और सात्विक जीवन पद्धति का ही पुनरुद्धार था।यह श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्विक आहार और विहारका ही पुनर्जागरण था।जब विदेशी मिशनरियां वनवासी समाज को यह समझा रही थीं कि उनका अतीत अंधकारमय था, तब बिरसा ने उन्हें उनके पुरखों के गौरव, रामायण और महाभारत के प्रसंगों से जोड़कर आत्मगौरव की अनुभूति कराई। मिशनरियों द्वारा किए जा रहे छद्म धर्मांतरण को रोकने के लिए बिरसा मुंडा ने अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरवबोध जगाया। उन्होंने वनवासियों को स्मरण कराया कि उनका मूल इतिहास वेदों और पुराणों की संस्कृति से जुड़ा है, न कि विदेशी आक्रांताओं से।उन्होंने स्पष्ट किया कि जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार ईश्वरीय है, जिसे कोई भी विदेशी सत्ता नहीं छीन सकती। भारतीय परंपरानुसार जब–जब समाज में धर्म की हानि होती है, तब–तब लोक चेतना किसी महापुरुष के माध्यम से प्रकट होती है। छोटानागपुर की धरती पर बिरसा मुंडा का प्राकट्य इसी दैवीय सिद्धांत का क्रियान्वयन था।ब्रिटिश हुकूमत के फॉरेस्ट एक्ट (वन कानून) ने वनवासियों को उनकी ही भूमि पर दास बना दिया था। इसके विरुद्ध बिरसा मुंडा ने नारा दिया– ष्अबूआ दिशुम रे अबूआ राजष अर्थात हमारे देश में हमारा राज। यह उद्घोष महर्षि चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित स्वराज्यऔर सुराजकी अवधारणा का ही जनजातीय रूपांतरण था। 1899–1900 का उलगुलान केवल कर न देने का आंदोलन नहीं था, बल्कि वह अपनी संस्कृति, स्वत्व और स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा गया एक पवित्र धर्मयुद्धथा। डोम्बारी बुरु की पहाड़ियों पर हुआ रक्तपात इस बात का साक्षी है कि वनवासी समाज ने अपनी स्वतंत्रता की वेदी पर हंसते–हंसते प्राणों की आहुति दे दी, किंतु विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं की।

भगवान बिरसा मुंडा का कालखंड उस समय का है, जब संपूर्ण भारत औपनिवेशिक दमन चक्र में पिस रहा था। ऐसे समय में उन्होंने नारा दिया–

महारानी राज तुंडू जाना ओरो अबूआ राज एते जाना।

अर्थात –महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो।

यह उद्घोष कौटिल्य के अर्थशास्त्रमें वर्णित विदेशी शासन (वैराज्य) की विभीषिका और स्वराज्यकी अनिवार्यता का साक्षात प्रमाण है। चाणक्य ने लिखा था कि विदेशी राजा प्रजा का केवल शोषण करता है, वह कभी प्रजा से अनुराग नहीं रख सकता। बिरसा मुंडा का अबूआ राजइसी चाणक्यीय नीति का जनजातीय संस्करण था। इस प्रकार,1899–1900 का उलगुलान केवल तीरों और बंदूकों का टकराव नहीं था। वह दो दर्शनों का महासंग्राम था– एक ओर पश्चिम की साम्राज्यवादी, शोषक और उपभोक्तावादी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर भारत की प्रकृतिपोषक, त्यागमयी और स्वाभिमानी वनवासी संस्कृति थी। डोम्बारी बुरु की पहाड़ियों पर जब महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों वनवासियों ने ब्रिटिश सेना की गोलियों के सामने सीना तान दिया, तब उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए अपनी धरती आबा (धरती माता) और स्वधर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन रांची के कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रहस्यमयी परिस्थितियों में वीर बिरसा मुंडा का प्राणांत हो गया, किंतु वे एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए, जो आज भी भारत की अखंडता की रक्षा कर रही है। आज जब वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संकट और सांस्कृतिक विखंडन की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, तब भगवान बिरसा मुंडा का दर्शन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसके साथ सह–अस्तित्व ही मानवता को बचा सकता है, यही बिरसा के उलगुलान का अंतिम संदेश था।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, गुरुवार 15 अक्टूबर 2026

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: १२ हजार रुपये रिश्वत लेते एकलव्य स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार

भुवनेश्वर १४/१० (संवाददाता): ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के प्रिंसिपल को रिश्वत लेने के आरोप में गिर तार किया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय में कार्यरत एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए उसके नाम की सिफारिश करने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में बातचीत के दौरान आरोपी 12 हजार रुपये लेने के लिए तैयार हो गया। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया और उसी दिन जाल बिछाकर प्रिंसिपल को कथित तौर पर 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। नौकरी की अवधि बढ़ाने के बदले मांगी रिश्वत सीबीआई के अनुसार, नुआपाड़ा जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कार्यरत एक महिला एएनएम की सेवा अवधि बढ़ाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि विद्यालय के प्रिंसिपल ने महिला की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए उसके नाम की सिफारिश करने के बदले 20 हजार रुपये की मांग की। शिकायत में कहा गया कि संबंधित कार्य के लिए प्रिंसिपल ने रिश्वत की शर्त रखी थी। यह मामला किसी नई नियुक्ति से संबंधित नहीं था, बल्कि विद्यालय में कार्यरत एएनएम की सेवा अवधि बढ़ाने की सिफारिश से जुड़ा था।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों की जांच शुरू की और मामले में कार्रवाई करने का निर्णय लिया। योजनाएं खोजें 20 हजार की मांग, 12 हजार में हुआ सौदा जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल ने शुरुआत में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के बाद वह 12 हजार रुपये लेने के लिए तैयार हो गया। इस तरह कथित रिश्वत की रकम में आठ हजार रुपये की कमी हुई। सीबीआई के अनुसार, समझौते के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 12 हजार रुपये स्वीकार करने पर सहमति जताई।

इसके बाद जांच एजेंसी ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सीबीआई की टीम ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच तय हुए भुगतान को लेकर कार्रवाई की योजना तैयार की। बुधवार को ही जांच एजेंसी ने प्रिंसिपल को कथित तौर पर रिश्वत स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। गुरुवार को सीबीआई की ओर से इस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की गई। योजनाएं खोजें रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया प्रिंसिपल सीबीआई ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की गई थी। इस दौरान प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता से 12 हजार रुपये की रिश्वत कथित तौर पर स्वीकार की। इसी समय सीबीआई की टीम ने उसे पकड़ लिया। योजनाएं खोजें एजेंसी के मुताबिक, आरोपी को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि, ट्रैप कार्रवाई में शामिल अधिकारियों, मौके की विस्तृत परिस्थितियों और बरामदगी से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जांच एजेंसी ने फिलहाल आरोपी की गिर तारी और मामले की जांच जारी रहने की पुष्टि की है। आरोपी प्रिंसिपल का नाम नहीं हुआ सार्वजनिक इस मामले में सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक सूचना में आरोपी प्रिंसिपल की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। एजेंसी ने केवल इतना बताया है कि आरोपी नुआपाड़ा जिले के

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। उसके खिलाफ एक एएनएम की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए सिफारिश करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोपी की उम्र, सेवा अवधि और अन्य व्यक्तिगत विवरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के प्रिंसिपल का नाम या अन्य पहचान संबंधी जानकारी देना उचित नहीं होगा। एएनएम की सेवा अवधि बढ़ाने से जुड़ा था मामला ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी एएनएम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रशिक्षित कर्मचारी होती हैं। एएनएम सामान्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य करती हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष महत्व होता है। नुआपाड़ा के इस मामले में संबंधित महिला की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल की सिफारिश आवश्यक बताई गई थी।

हालांकि, महिला की नियुक्ति किन शर्तों पर हुई थी और उसकी सेवा अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई जानी थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या हैं? स्कूल खोजें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल का हिस्सा हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ शिक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका संचालन जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सहायक कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नुआपाड़ा के विद्यालय में सामने आया रिश्वत का मामला इसी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। सरकारी संस्थानों में रिश्वतखोरी गंभीर मामला किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान में नियुक्ति, सेवा विस्तार या प्रशासनिक कार्य के बदले रिश्वत मांगना गंभीर आरोप माना जाता है। इस प्रकार की गतिविधियां कर्मचारियों के अधिकारों और संस्थागत पारदर्शिता से संबंधित सवाल पैदा करती हैं। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी होनी है, तो उसमें अवैध भुगतान की मांग नहीं की जा सकती। नुआपाड़ा में सामने आए मामले में प्रिंसिपल पर इसी प्रकार की मांग करने का आरोप लगा है। हालांकि, आरोपी के विरुद्ध आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। सीबीआई कर रही मामले की आगे जांच प्रिंसिपल को पकड़ने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। योजनाएं खोजें जांच के दौरान रिश्वत की कथित मांग, सेवा अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रशासनिक दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एजेंसी यह भी जांच सकती है कि शिकायत में बताए गए काम को लेकर प्रिंसिपल की वास्तविक भूमिका क्या थी। हालांकि, अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता या किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क से संबंध होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी सामने नहीं आई है। सेवा विस्तार की प्रक्रिया पर उठे सवाल इस घटना ने आवासीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। कर्मचारियों को अपने रोजगार से संबंधित वैध कार्यों के लिए रिश्वत देने की स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कथित रिश्वत मांगने की जानकारी जांच एजेंसी तक पहुंचाई। इसके बाद सीबीआई की कार्रवाई में आरोपी प्रिंसिपल को पकड़ा गया। इससे सरकारी कार्यों में रिश्वत मांगने की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई के महत्व का पता चलता है। जांच के बाद स्पष्ट होगी पूरी स्थिति ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में हुई इस कार्रवाई में अब तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल की गिर तारी की पुष्टि हुई है। सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने एएनएम की सेवा अवधि बढ़ाने की सिफारिश के बदले पहले 20 हजार रुपये मांगे और बाद में 12 हजार रुपये लेने के लिए तैयार हो गया। योजनाएं खोजें इसके बाद जांच एजेंसी ने सात अक्टूबर को मामला दर्ज कर ट्रैप कार्रवाई की। सीबीआई ने आरोपी को 12 हजार रुपये की कथित रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ने की जानकारी दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ लगाई गई कानूनी धाराओं, न्यायालय में पेशी और आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

एनजेडपी में रात्रिचर पशु गृह बंद, पर्यटक मायूस

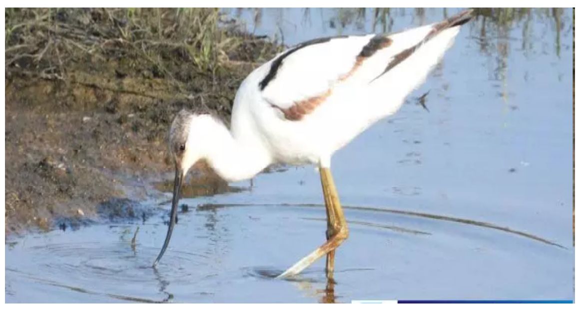

बारंगा १४/१० (संवाददाता): यहां नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (एनजेडपी) के प्रमुख आकर्षणों में से एक–नोक्टर्नल एनिमल हाउस–तीन साल से अधिक समय से बंद है, जिससे पर्यटक निराश हैं। नवीनीकरण और मर मत का काम तीन साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन कथित तौर पर अधिकारियों की ओर से गंभीरता की कमी के कारण परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे चिड़ियाघर आने वाले पर्यटक इस सुविधा को देखने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। आगंतुकों के लिए उपहार के रूप में 2015 में चिड़ियाघर के स्थापना दिवस पर तत्कालीन वन मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा द्वारा आधुनिक तकनीक से सुसज्जित रात्रिचर पशु घर का उद्घाटन किया गया था। एनजेडपी, देश के प्रमुख प्राणी उद्यानों में से एक, अपने वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन के लिए पूरे वर्ष आगंतुकों को आकर्षित करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने और बेहतर प्रबंधन की सुविधा के लिए, चिड़ियाघर को सरीसृप पार्क, मांसाहारी, जलीय और स्थलीय पक्षियों और उत्तरपूर्वी परिदृश्य जैसे वर्गों में विभाजित किया गया है। रात्रिचर पशु आवास प्रमुख आकर्षणों में से एक था। अन्य चिड़ियाघरों में समान सुविधाओं की तुलना में बाड़े का डिज़ाइन विशिष्ट है। बाड़े को रात की स्थिति को फिर से बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे वहां रहने वाले रात्रिचर जानवरों को प्राकृतिक रूप से घूमने की अनुमति मिल सके।

इस सुविधा में कई रात्रिचर प्रजातियाँ शामिल थीं, जिनमें भारतीय उड़न गिलहरी, सिवेट बिल्लियाँ, उल्लू, पैंगोलिन, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ, चमगादड़ और स्लॉथ भालू शामिल थे। आगंतुक मंद रोशनी से जगमगाते छोटे कांच के बाड़ों के माध्यम से जानवरों को करीब से देख सकते थे, जिससे उन्हें रात के समय एक अनोखा अनुभव मिलता था। हालाँकि, मर मत और नवीनीकरण के लिए बाड़ा पिछले तीन से चार वर्षों से बंद है। नतीजतन, आगंतुक चिड़ियाघर के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक का आनंद लेने में असमर्थ रहे हैं। जबकि कथित तौर पर एनजेडपी को एक विश्व स्तरीय प्राणी उद्यान के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, रात्रिचर पशु घर के लंबे समय तक बंद रहने से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह अधिकारियों की ओर से प्रतिबद्धता की कमी या लापरवाही के कारण है। सुविधा के बाहर आगंतुकों को सूचित करने वाला कोई प्रमुख नोटिस बोर्ड भी नहीं है कि यह बंद है।

एमसीएल ने सुंदरगढ़ जिले में पांच सीएसआर परियोजना हेतु किया २२.६४ करोड़ के एमओयू

संबलपुर १४/१० (संवाददाता): महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत सुंदरगढ़ जिला प्रशासन के साथ 22.64 करोड़ की पाँच विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं में काटा बांध (4.32 करोड़), ब्राह्मणी बांध (3.98 करोड़) तथा अब्दुल हुसैन बांध (2.69 करोड़) का पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण; हेमगीर ब्लॉक के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मीठे पानी की अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देना (3.81 करोड़); तथा तलसरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का नवीनीकरण, सुधार

एवं निर्माण (?.84 करोड़) शामिल हैं। समझौता ज्ञापनों पर एमसीएल के महाप्रबंधक (सीएसआर) तथा सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी ने हस्ताक्षर किए। मिशन अमृत सरोवर के उद्देश्यों के अनुरूप, जल निकायों के पुनरुद्धार से जल संरक्षण को सुदृढ़ करने, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने का लक्ष्य है। इन पहलों से जनसुविधाओं में वृद्धि के साथ–साथ मनोरंजन, लघु पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के विकास के अवसर भी सृजित होंगे।

प्रस्तावित कार्यों में तटबंधों का संरक्षण, पथों का निर्माण, स्नान घाटों का विकास, पत्थर की पिचिंग, रेलिंग एवं बैठने की व्यवस्था, विद्युत संबंधी कार्य तथा उद्यानिकी विकास शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रस्तावित मीठे पानी की अंतर्देशीय मत्स्य पालन परियोजना से 700 से अधिक लघु किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को लाभ मिलने की उमीद है। मत्स्य पालन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 50 नए तालाबों का निर्माण तथा 20 मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिला स्व–सहायता मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, एक एक्वा बिजनेस स्कूल तथा एक मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन भी प्रस्तावित है। इन पहलों का उद्देश्य क्षमता विकास, उद्यमिता तथा सतत आय सृजन को प्रोत्साहित करना है। इन पहलों के माध्यम से एमसीएल का लक्ष्य जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना, सतत आजीविका को बढ़ावा देना, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करना तथा सुंदरगढ़ जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। ये परियोजनाएँ समावेशी विकास के प्रति एमसीएल की प्रतिबद्धता को दोहराती हैं और इसके परिचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्कूल हॉस्टल में 35 लड़कियाँ बीमार पड़ गईं

बारीपदा १४/१० (संवाददाता): मयूरभंज के बडासाही ब्लॉक के अंतर्गत मनत्री में स्स्ष्ठ गर्ल्स हाई स्कूल हॉस्टल में रहने वाली 35 छात्राएं मंगलवार देर रात संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गईं। सूत्रों ने बताया कि छात्राओं ने हॉस्टल में रात के खाने में चावल और सब्जी खाई थी और सो गईं। लगभग एक घंटे बाद, उनमें से कुछ को बेचैनी महसूस होने लगी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे। कुछ ही मिनटों में, कई अन्य छात्राओं में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देने लगे। प्रभावित छात्राओं की सं या बढ़ने पर, हॉस्टल वार्डन ने उन्हें इलाज के लिए मनत्री स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। खबरों के अनुसार, कुछ छात्राओं की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बडासाही क युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया, जहां उनके इलाज के लिए एक मेडिकल टीम तैनात की गई।

डॉक्टरों ने कहा कि प्रभावित छात्राओं को तुरंत इलाज मिला और उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने कहा कि इस घटना के पीछे फूड पॉइजनिंग या दूषित पीने का पानी हो सकता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मनाया 72वाँ वन्यजीव सप्ताह

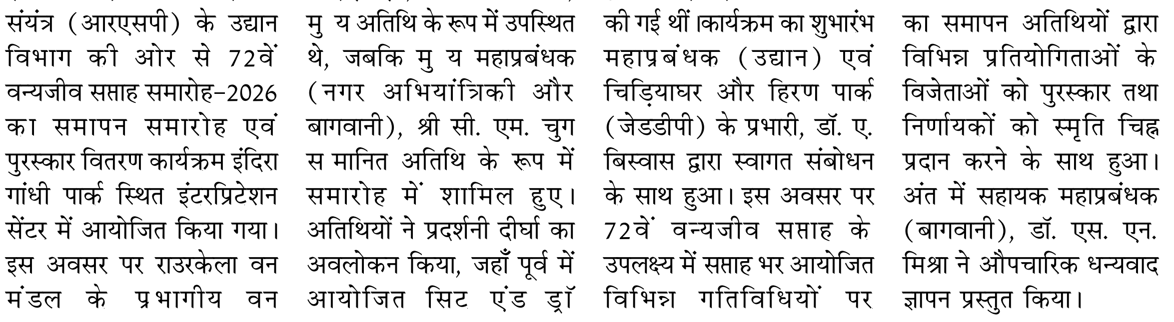

राउरकेला १४/१० (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के उद्यान विभाग की ओर से 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह–2026 का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम इंदिरा गांधी पार्क स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राउरकेला वन मंडल के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), आईएफएस, श्री रविकांत मीणा, मु य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि मु य महाप्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी और बागवानी), श्री सी. एम. चुग स मानित अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। अतिथियों ने प्रदर्शनी दीर्घा का अवलोकन किया, जहाँ पूर्व में आयोजित सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई थीं।कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक (उद्यान) एवं चिड़ियाघर और हिरण पार्क (जेडडीपी) के प्रभारी, डॉ. ए. बिस्वास द्वारा स्वागत संबोधन के साथ हुआ। इस अवसर पर 72वें वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में सप्ताह भर आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर आधारित एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। समारोह का समापन अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार तथा निर्णायकों को स्मृति चिह्न प्रदान करने के साथ हुआ। अंत में सहायक महाप्रबंधक (बागवानी), डॉ. एस. एन. मिश्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

पड़ोसी ने 35 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

अंगुल १४/१० (संवाददाता): बंटाला इलाके के निमचक में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बंटाला गांव के व्यवसायी सुसांता प्रधान के रूप में की गई। लोग खोजें बंटाला पुलिस स्टेशन के आईआईसी विभूति प्रधान ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुशांत अपने पड़ोसी, एक सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी के घर गए थे। ऐसा संदेह है कि दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी, जिसके बाद सेवानिवृत्त सेना के जवान ने कथित तौर पर सुसांता पर गोली चला दी।गोली उसके सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें बंटाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक लाइसेंसी बंदूक जब्त की गई है। घटना के बाद से आरोपी पड़ोसी कथित तौर पर फरार है।

MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)
जागृति विहार, बुर्ला - 768 020, जिला - सम्बलपुर, ओडिशा
दूरभाष (ईपीएबीएक्स) : 0663-2542461 से 469, वेबसाइट : http://www.mahanadicoal.in

सूचना

सामानों, कार्यों एवं सेवाओं के क्रय हेतु सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी सभी निविदाएँ कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.coalindia.in**/संबंधित सहायक कंपनी (एमसीएल, **www.mahanadicoal.in**), सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://coalindiatenders.nic.in** एवं सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://eprocure.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल **https://gem.gov.in** के माध्यम से भी ये क्रय उपलब्ध है।
R-5314